सरकार और उत्पादक सदस्यों के माध्यम से शेयर पूंजी के रूप में जुटाया जाना होगा। तथापि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन०सी०डी०सी०) राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले शेयर पूंजी के अंशदान के एक भाग को प्रतिपूर्ति कर राज्य सरकारों की सहायता करता है। इन यूनिटों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा लेवी मुक्त चीनी के कोटे की अधिक प्रतिशतता आदि जैसे प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं।

Coconut as Oilseed

776. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that coconuts are not treated as "Oilseeds" though they yield coconut oil;

(b) if so, what are reasons therefor;

(c) whether Government are aware that due to this concept, the amount reserved for the Oilseeds Development during the seventh plan is not available to coconut growers; and

(d) if so what steps Government propose to take to include coconut in the item of oilseeds?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (b) Coconut is a perenniel plantation crop yielding edible oil.

(c) and (d) For coconut a statutory Board has been set up under an Act of Parliament and separate funds are provided for its development.

Against an allocation of Rs. 439.76 lakhs during the Sixth Plan a total sum of Rs. 900 lakhs is likely to be available during the Seventh Plan for coconut development programmes.

उत्तर प्रदेश में संयुक्त कृषि सहकारी समितियां

777. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी संयुक्त कृषि सहकारी समितियां पंजीकृत की गयी हैं ;

(ख) इनमें सहकारी समितियां अभी भी सक्रिय हैं तथा लाभ में चल रही हैं; और

(ग) राज्य में संयुक्त कृषि सहकारी आंदोलन की दुःस्थिति के क्या कारण हैं तथा इसके निवारण के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (श्री जी० एस० डिल्लो): (क) और (ख) 30 जून, 1981 को उत्तर प्रदेश में 1332 संयुक्त कृषि सहकारी समितियां थीं, जिसके लिए जानकारी उपलब्ध है। इनमें से कार्य कर रही सहकारी समितियों की संख्या 634 थीं, जिसमें लाभ पर चलने वाली 377 समितियां शामिल हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश के सातवीं पंचवर्षीय योजना के कागजात में सहकारी कृषि के संबंध में 4.85 लाख के परिव्यय से निम्नलिखित व्यवस्था की गई है :—

> सहकारी कृषि समितियों का सघन सर्वेक्षण शुरू किया गया है। यह प्रस्ताव किया गया है कि एकत्र जानकारी का विश्लेषण करने के बाद प्रमाणित बीजों के उत्पादन, आधुनिक कृषि उपस्करों के प्रयोग तथा परीक्षण, जिससे उत्पादन में वृद्धि, होगी के साथ कृषि कार्यक्रम का समन्वय करने के लिए विस्तृत योजनाएं बनाई जाएं।

Representation by Mini Steel Plants

778. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it Is a fact that Gov-